सं.ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांक: 1st जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित नवम्बर, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनु पी० मथाई

(अनु पी. मथाई)
सलाहकार (प्रशा. एवं आईईआर)
दूरभाषः 23092449

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव(एफएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
15. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
16. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आर्थिक कार्य विभाग।
17. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष। संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव बीसी एण्ड आईईआर/संयुक्त सचिव(निवेश)/सलाहकार (सीएंडएसी/एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएएए।
19. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
20. गार्ड फाइल – 2021

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः नवम्बर, 2020 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में दर्ज रिकार्ड गिरावट से 2020-21 की दूसरी तिमाही में प्रभावशाली बहाली विन्यस्त की है, जिससे ज्ञात होता है कि आर्थिक गतिविधियों की बहाली गतिशील हो रही है। 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी (-)7.5 प्रतिशत संकुचित हुई है जो 2020-21 की पहली तिमाही में (-)23.9 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में काफी कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सरकार की समर्थनकारी नीतियों के परिणामस्वरूप सितम्बर से नवम्बर, 2020 में पहले से काफी अधिक आर्थिक गतिविधियां हुईं। यह उच्च आवृत्ति संसूचकों जैसे कि पीएमआई विनिर्माण, पीएमआई सेवाओं, बिजली की खपत, यात्री वाहनों की बिक्री, ट्रैक्टरों की बिक्री, ई-वे बिलों, जीएसटी संग्रहणों, रेलवे मालभाड़ा, कार्गो यातायात, घरेलू विमानन यात्रियों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह की वृद्धि से स्पष्ट होता है। संभवतः भौतिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखने की स्थिति से ऊब जाने के कारण उत्पन्न कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की घटना को छोड़कर, भारत इस वर्ष के अंत तक तीव्र गति से बहाली की स्थिति तथा कोविड-पूर्व के स्तरों पर पहुंचने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण सूचना का ब्यौरा सारणीबद्ध रूप से अनुबंध में दिया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 विश्लेषणों और सूचियों को उपलब्ध कराने की अग्रणी कंपनी, मोर्गन स्टैले केपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) जिसकी वैश्विक निवेशकों के बीच अच्छी पैठ है, ने 10 नवम्बर, 2020 को अपनी विभिन्न सूचियों में कई भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। ऐसा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एफपीआई नीतियों में बदलाव करने के कारण हुआ है जिसके द्वारा अमुक कंपनी में कुल एफपीआई निवेश की सांविधिक सीमा को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर सेक्टर की उच्चतम सीमा तक कर दिया है। इन नई वृद्धियों से आशा है कि भारत में लगभग 2.55 बिलियन अमरीकी डॉलर का परोक्ष अंतर्वाह होगा। नवम्बर माह में भी सर्वाधिक मासिक एफपीआई अंतर्वाह दर्ज किया गया है जो पहली बार बढ़कर 62,782 करोड़ रुपए हुआ है जो मुख्य रूप से इक्विटी में निवेशों के कारण हुआ है।

2.2 (क) आर्थिक कार्य विभाग तथा भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम (एसपीएमसीआईएल) के बीच संगठन के निष्पादन में सुधार लाने हेतु परस्पर सहमत लक्ष्यों की तुलना में प्रमुख चुनिंदा प्राचलों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन को मापने के लिए 2020-21 के लिए 11 नवम्बर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।